1	2	3	4
10.	EAST KAMENG	VLPT SEPPA	VLPTs CHAYANGTAJO SEUOSA PIPU DIPU/ NYAPIN (in L. Subansfari Dt.)
11.	TAWANG	VLPT TAWANG	VLPT MUKTO

Note-1. HPT is of 1 KM power, LPT of 100 W power and VLPT of 10 W power.
2. Service range of the HPT is 60 km and that of the LPTs and VLPTs about 25 km and 8 km, respectively.

नाबार्ड द्वारा गठित समिति

1205. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को "नाबार्ड" द्वारा ग्रामीण बैकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा किए जाने का विचार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च की गई धनराशि

1206. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार द्वारा वर्ष 1991 में देश में खर्च की गई कुल धनराशि का 16.3 प्रतिशत भाग असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च किया गया था जबकि वर्ष 1995 में यह राशि बढ़कर 29.11 प्रतिशत हो गई;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच हैं कि इन वर्षो के दौरान इन कर्मचारियों की संख्या में कमी आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की संख्या वर्ष 1991 में और मार्च 1995 के अंत में कितनी-कितनी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के कुल व्यय में संघ शासित राज्यों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (सिविलियन) के वेतन और भत्तों पर हुए व्यय का प्रतिशत वर्ष 1990-91 में 8.33% से घटकर वर्ष 1994-95 में 8.18% रह गया।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की प्राक्कलित संख्या जो मार्च, 1991 में 40.82 लाख थी घटकर मार्च, 1985 , में 38.48 लाख रह गयी।

Functioning of Public Sector Banks Question

1207. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in Public Sector Banks, most sensitive functions like proposals for sanction of loans, compromise/write off, engagement/release/purchase/sale of properties etc. have been vested with Management Committee inplace of Board;